All India Small and Medium Newspapers Federation, (AISMNF) urged the Government to withdraw the Press and Registration of Books (Amendment) Bill; and

(b) if so, the details thereof and reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) In the memorandum submitted to the Prime Minister, the All India Small and Medium Newspapers Federation, *inter alia*, has taken strong exception to certain provisions of the Press and Registration of Books (Amendment) Bill, 1988.

(b) Government have taken note of the views of the Federation.

Setting up of Sate Finance Commission

2676. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Council for Local Government and Urban Development have since suggested some suitable proposal to amend the Constitution of the country to provide for setting up State Finance Commission for sytematic devolution of funds from the State Government to local bodies:

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether the Council also suggested that local bodies be permitted to impose property tax on the Central and State Government properties; and

(d) if so, reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Yes. The resolutions have been forwarded to State Governments for their reaction

(c) Yes.

(d) Article 285 of the Constitution exempts the properties of the Union Government from the property tax imposed by State or any authority within the State, and that includes local bodies.

Creation of employment in rural areas

2677. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have fixed a target of creating about 245 million mandays of employment in the rural areas during the Seventh Five Year Plan; and

(b) to what extent the target has since been achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) A target for generating 2458 million mandays of employment in rural areas under National Rural Employment Programme and Rural Landless Employment Guarantee Programme (1445 million mandays under NERP & 1013 million mandays under RLEGP) has been fixed for the seventh Plan (1985-90). As against this, employment generated under these Programmes so far is 2384.38 million mandays.

राज्यों को तिलहनों की आपूर्ति

2678. **श्रीमती रत्न कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना को कार्यान्वित कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को वांछनीय किस्म के बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कई राज्यों में तिलहन उपलब्ध न होने के कारण 1988 के खरीफ मौसम के दौरान

तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में एक अधिनियम बनाकर ऐसी नीति अपनाने का विचार रखती है कि वह विभिन्न राज्यों से तिलहन एकत्र करने और फिर सभी राज्यों को आवश्यकतानुसार उन्हें इनका समय पर वितरण करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रजनक बीजों के उत्पादन की व्यवस्था करती है। उसके बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उन बीजों का बहुलीकरण करना राज्य सरकारों का काम है। इसके अतिरिक्त, राज्यों की आवश्यकता पूरी करने में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी केन्द्रीय बीज उत्पादक ऐजेंसियां भी बीजों का उत्पादन करती है ;

(ग) यह कहना उचित नहीं है कि बीज उपलब्ध न होने के कारण कई राज्यों में तिलहनों के उत्पादन में कमी आई है। दूसरी तरफ 1988-89 के दौरान तिलहनों का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है जो लक्ष्य स्तर से अधिक होगा।

(घ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Payment of compensation by Khanna Improvement trust

2679. SHRIMATI PRATIBHA SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Khanna Improvement Trust, Ludhiana, Punjab had acquired land in 1973 under Section 36 of the Punjab Town Improvement Act, 1922 measuring 345 Kanals and Marlas for development of residential-cum-commercial centres but the compensation has not so far been paid;

(b) what are the reasons for not paying compensation so far;

(c) whether it is also a fact that according to the Haryana Improvement Trust Act, if compensation is not paid within a period of 8 years; the scheme of acquisition of land is collapsed; and

(d) if so, whether Government shall give possession back to the owners on the ground that it has failed to pay compensation for the last 16 years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

एल्यूमिनियम की कीमत और उसके वितरण पर नियंत्रण

2680. **श्री ईश दत्त यादव : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैम्बर आफ इण्डियन ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री ने सरकार से मांग की है कि एल्यूमिनियम की कीमत और वितरण पर सरकारी नियंत्रण जारी रहना चाहिए और हिन्डाल्को-बाल्को, नाल्को, ईडाल और माल्को को अपनी-अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने की अनमति प्रदान की जाए और उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली और अन्य आवश्यक कच्चा माल सप्लाई किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र में नाल्को व बाल्को ने और प्रायवेट सैक्टर में हिन्डाल्को ने ग्रहीत बिजलीघर लगाकर अपने आपको बिजली की कमी से मुक्त